

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर

अपील संख्या - 41/22

GCMS NO 2022/68

1. मुरारी पुत्र गोविन्द
2. कालू पुत्र कन्हैया
3. सोनू पुत्र कन्हैया
4. तीजो बेवा कन्हैया समस्त जातियान बैरवा निवासीयान ग्राम अमावरा तहसील बामनवास जिला सवाई माधोपुर

अपीलांट

वनाम

1. नाथ्या पुत्र गेन्दया
2. मुरया दत्तक पुत्र मूल्या
3. नन्दलाल पुत्र नाथ्या
4. लक्ष्मण पुत्र नाथ्या जातियान बैरवा निवासीयान ग्राम अमावरा तहसील बामनवास जिला सवाई माधोपुर
5. प्रेम पुत्री गेन्दया पत्नि कजोडया रति बैरवा हालवासी गुढाचन्द्रजी
6. लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार तहसील बामनवास

रेस्पो0

(अपील विरुद्ध मु0नं0 2/12 निर्णय व डिक्री दिनांक 13.5.16 न्यायालय उप जिला कलेक्टर बामनवास)

अभिभाषक अपीला0 श्री श्याम मोहन शर्मा


अभिभाषक रेस्पो0 श्री आर.डी.त्रिवेदी, श्री योगेश शर्मा

दिनांक 14.5.2026

निर्णय

प्रस्तुत अपील अपीला0 की ओर से अंतर्गत धारा 223 विरुद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 13.5.16 न्यायालय उप जिला कलेक्टर बामनवास पेश की है।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में वादी/रेस्पो0 संख्या 1 द्वारा वाद पत्र इन्द्राज दुरुस्ती विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा विरुद्ध मूल्या दत्तक पुत्र मूल्या व श्रीमती धापा पत्नि गेदया जाति बैरवा इस आशय का पेश किया कि वादी और प्रतिवादी संख्या 2 एक ही पूर्वज की संताने है एवं प्रतिवादिया संख्या 3 वादी की मां है। वादी के सगे बाबा जीवण दो भाई थे। दुसरे भाई का नाम नानगा था एवं जीवण के दो लडके गेदया व मूल्या हुए। चूकि मूल्या के कोई संतान नही थी इसलिए मूल्या ने सामाजिक रितीरिवाज के अनुसार मूस्या पुत्र गेदया को गोद ले लिया। मूल्या व उसकी पत्नि फाबूली का निधन हो चुका है। मूल्या की समस्त चल अचल सम्पति पर प्रतिवादी संख्या 2 मूस्या ही काबिज है व मूल्या की खातेदारी की भूमि मे मूस्या का नाम बतौर खातेदार दर्ज हो चुका है। वादी के सगे पिता गेदया के दो पुत्र वादी स्वयं व मूस्या हुए दूसरा पुत्र मूस्या अपने चाचा मूल्या के यहाँ गोद चला गया इस प्रकार जीवण की खातेदारी भूमि मे हिस्सा 1/2 वादी नाथ्या व उसकी मां प्रतिवादी संख्या 3 का है व 1/2 हिस्सा मूल्या के दत्तक पुत्र मूस्या का है। इस प्रकार राजस्व रिकार्ड मे इन्द्राज किया


राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

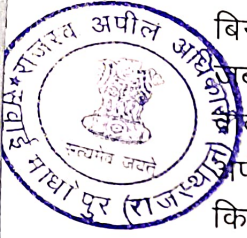
जाना आवश्यक है। वादी के पिता व प्रतिवादिया संख्या 3 के पति गेदया का निधन अय से करीब 40 वर्ष पूर्व हो चुका है। गेदया की समस्त चल अचल सम्पत्ति पर वादी और उसकी मां श्रीमती धापा ही बतौर स्वामी काबिज है। वादी ने अपने नाम खातेदारी विरासत का नामा खुलवाने के लिए प्रतिवादी संख्या 1 से निवेदन किया कि जमाबंदी में वादी के पिता का नाम गेदया के स्थान पर गोविन्दा दर्ज मिला वादी के पिता का नाम गेदया ही है। संबंधित सरकारी कर्मचारी की गलती से जमाबंदी में गेदया के स्थान पर गोविन्दा दर्ज हो गया है जिसको भी दुरुस्त किया जाना आवश्यक है। हाल खसरा न० 2823,2824,2846,2849 एवं 2850 कुल किता 6 कुल रकबा 1.22 है० वाके ग्राम अमावरा तहसील बामनवास स्थित है। जिसमें 1/2 हिस्सा वादी एवं उसकी मां प्रतिवादिया संख्या 3 का 1/2 एवं 1/2 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 2 मूस्या का है। वादी द्वारा सरकारी रिकार्ड में जहाँ भी खातेदार गोविन्दा पुत्र जीवण अंकित है उसके स्थान पर गेदया पुत्र जीवण अंकित किये जाने व उक्त आराजी का मीटस एण्ड वाउन्डस में विभाजन किया जाना आवश्यक है। अतः आराजी खसरा न० 2823,2824,2846,2849 एवं 2850 कुल किता 6 कुल रकबा 1.22 है० वाके ग्राम अमावरा तहसील बामनवास की खातेदारी व अन्य सरकारी रिकार्ड में जहाँ जहाँ भी खातेदार गोविन्दा पुत्र जीवण अंकित है, का इन्द्राज दुरुस्त किया जाकर उसके स्थान पर गेदया पुत्र जीवण अंकित किये जाने व रिकार्ड दुरुस्ती की जावे तथा उक्त आराजीयात का मीटस एण्ड वाउन्डस के आधार पर विभाजन किया जाकर 1/2 हिस्से की खातेदारी वादी व उसकी मां प्रतिवादिया संख्या 3 के नाम व शेष 1/2 हिस्से की खातेदारी प्रतिवादी संख्या 2 मूस्या के नाम दर्ज की जाकर मौके पर विभाजित किये जाने के आदेश प्रदान किये जावे। इस प्रकार की इस्तदुआ अधिनस्थ न्यायालय से वादी/रेस्पोंड संख्या 1 द्वारा गई। अधिनस्थ न्यायालय में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ने अधिनस्थ न्यायालय में उपस्थित होकर राजीनामा पेश किया। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा राजीनामा एवं दस्तावेजात का अवलोकन किया जाकर मुताबिक राजीनामा वादी का वाद पत्र डिक्री किया गया। जिससे व्यथित होकर अपीलांट द्वारा यह अपील धारा 96 सीपीसी के प्रार्थना पत्र के साथ इस न्यायालय में पेश की गई है।


अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। रेस्पोंड को नोटिस जारी कर तलब किया गया। बहस उभयपक्ष अधिवक्तागण की अपील पर सुनी गई।

अपीलांट के अधिवक्ता ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री रूयेदाद मिसल एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों एवं तथ्यों से परे होने से निरस्त योग्य है। अदालत मातहत ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर उपरोक्त अपीलाधीन आदेश साक्ष्य एवं मौके व कब्जे के विपरीत जाकर अपीलांट से छिपाते हुए धोखे में रखकर विधि विरुद्ध तरीके से कानूनी प्रावधानों के विपरीत जाकर पारित कर दी प्रतिवादीगण ने न्यायालय से साज कर जल्दबाजी में उपरोक्त निर्णय तहत न्यायालय से पारित कराया है। इसका सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में दर्ज अपीलांट के पिता गोविन्द पुत्र नानगा का नाम हजफ किये जाने का आदेश निराधार तथ्यों पर साक्ष्य के


राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

अभाव मे पारित किया है। वाद मे वर्णित आराजी अपीलांट के पिता एवं पूर्वज गोविन्द पुत्र नानगा की खातेदारी कब्जे काशत की भूमि है तथा उक्त आराजी पर अपीलांटगण अपने पिता के जीवनकाल से ही आज दिनांक तक काविज काशत रहकर लाभान्वित चले आ रहे है। तहत न्यायालय ने रेस्पोंडनेट ने आपस मे साजकर फर्जी राजीनामा पेश कर उक्त निर्णय व डिक्री विधि विरुद्ध तरीके से पारित की है इस कारण भी अपीलाधीन निर्णय खिलाफ कानून होने से निरस्तनीय है। वादी नाथ्या ने गोविन्दा के पुत्र मुरारी एवं अन्य शेष वारिसान को पक्षकार बनाये बिना मूल्या व धापा को पक्षकार बनाकर उक्त अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई है जबकि साबिक समस्त राजस्व रिकार्ड जमाबंदी सम्वत 2016-18, 2022-2025 से साबित था कि वाद मे वर्णित आराजी गोविन्दा बैरवा की खातेदारी कब्जे काशत की भूमि है। इस प्रकार अपीलाधीन निर्णय व सुनवाई के दौरान अपीलांटगण को किसी प्रकार का साक्ष्य सुनवाई का किसी प्रकार का अवसर प्रदान नहीं किया है। इस कारण अपीलाधीन निर्णय प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विपरीत होने से निरस्तनीय है। आवंटन आदेश दिनांक 18.7.1975 से भी गोविन्द पुत्र नानगा होने का तथ्य साबित है तथा गोविन्दा की विरासत का नामांकी विरासत का इस जमीन का नहीं खोला गया क्योंकि स्टे था। प्रार्थी को इसकी सूचना नहीं थी तथा प्रतिवादीगण रेस्पोंडनेट ने आपसी साजकर उक्त डिक्री का राजस्व रिकार्ड मे अंकन कराकर वाद मे वर्णित आराजी को जरिये रजिस्ट्री नन्दलाल व लक्ष्मण को कर दी। जबकि वरवक्त रजिस्ट्री केता नन्दलाल मौजूद ही नहीं था। वह तो विदेश मे था, इससे स्पष्ट है कि उक्त सम्पूर्ण कार्यवाही अपीलांटगण की खातेदारी कब्जे काशत की भूमि को हडपने की गरज से सम्पादित की गई है। इस प्रकार की डिक्री से कोई हक व अधिकार हासिल नहीं होते है तथा रेस्पोंडनेट का जो राजीनामा प्रस्तुत हुआ उसमे 1/2 हिस्से का खातेदार घोषित होने की हद तक किया है जबकि वादी नाथ्या द्वारा वाद पत्र विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा का था। जबकि तहत न्यायालय ने ना तो उक्त भूमि का बंटवारा किया ना किसी प्रकार की स्थाई निषेधाज्ञा जारी की। क्योंकि टीनेन्सी एक्ट के प्रावधानो के तहत यदि मौके पर जाकर बंटवारा स्कीम तैयार होती तो सब स्थिति पूर्व मे ही न्यायालय के समक्ष आ जाती। प्रकरण मे किसी प्रकार की कोई प्रारंभिक डिक्री जारी नहीं की गई तथा गोविन्दा की जगह एक मात्र निवेदन करने पर खातेदारी परिवर्तित की है इसके संदर्भ मे किसी प्रकार का कोई राजस्व रिकार्ड या मौखिक साक्ष्य या अन्य कोई दस्तावेजी साक्ष्य वादी द्वारा पेश नहीं की है ना ही तहत न्यायालय ने अपने निर्णय मे कोई विवेचना दी है, इस कारण अपीलाधीन निर्णय खिलाफ कानून होने से निरस्तनीय है। जीवण व नानगा दो आपस मे सगे भाई जीवण के दो पुत्र गेदया व मूल्या है मूल्या लाओलाद फोट हो चुका है तथा गेदया का पुत्र मुस्या, मूल्या के गोद चला गया तथा गेन्दया का एक पुत्र नाथ्या उसके पास रहा इसी अनुरूप नानगा के एक मात्र गोविन्दा तथा गोविन्दा के दो पुत्र अपीलांट मुरारी व कन्हैया रहे है कन्हैया फोट हो चुका जिसके कालू व सोनू तथा उसकी बेवा तीजो है जो कि अपीलांट है। वाद मे वर्णित आराजी गोविन्दा पुत्र नानगा की खातेदारी कब्जे काशत की आराजी है जिससे की जीवण के वारिसान का कोई संबंध वास्ता नहीं है। प्रतिवादीगण द्वारा की गई फर्जकारी की एफ आई आर दर्ज करा दी गई है इन तथ्यो पर गौर किये बिना उपरोक्त अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की है जो खिलाफ कानून होने से निरस्तनीय है। अपीलाधीन निर्णय व डिक्री से अपीलांटगण प्रत्यक्ष तौर




राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

पर एग्रीवड है तथा उक्त आराजीयात पर अपीलांटगण अपने पिता के जीवन काल से काबिज काशत रहकर लाभान्वित होते चले आ रहे हैं। रेस्पों ने आपस में साज करके उक्त निर्णय व डिक्री प्राप्त की है इस प्रकार के आदेश से रेस्पों को कोई हक एवं अधिकार हासिल नहीं होते हैं। तहत न्यायालय में अपीलांटगण को जानबूझकर पक्षकार नहीं बनाया है लिहाजा अपीलांटगण को अपील पेश करने की स्वीकृति दिया जाना न्यायोचित है। उपरोक्त अपीलाधीन निर्णय व डिक्री की जानकारी अपीलांटगण को दिनांक 8.5.22 को केता रेस्पों मौके पर आये और उन्होंने कि यह जमीन हमने खरीद ली है जब इस पर अपीलांट ने कहा कि ये तो मेरे पिता गोविन्दा की खातेदारी की जमीन है इस पर उन्होंने बताया कि तुम्हारे पिता का नाम हजफ न्यायालय से हो चुका है अब इस जमीन को मत जोतना। जिस पर अपीलांटगण द्वारा नकल प्रार्थना पत्र तहत न्यायालय में पेश कर दिनांक 12.5.22 को निर्णय व अन्य दस्तावेजात की नकल प्राप्त की गई जब जानकारी होने पर जानकारी के आधार पर अपील अन्दर मियाद धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत की गई है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री तहत न्यायालय निरस्त फरमाया जावे तथा वाद में वर्णित आराजीयात की पूर्ववत् रहे इन्द्राज अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे।

रेस्पों के अधिवक्ता ने बहस में तर्क दिया कि अपीलाधीन निर्णय व डिक्री वादी एवं प्रतिवादीगण द्वारा आपसी सहमति दिये जाने के आधार पर तहत न्यायालय द्वारा राजस्व लोक अदालत अमावरा में पारित की गई है। जिसकी कानूनन अपील पोषनीय नहीं है। अपीलांट अधिवक्ता का कथन मिथ्या है कि अधिनस्थ न्यायालय में वादी एवं प्रतिवादी द्वारा साजकर निर्णय व डिक्री पारित कराई है जबकि सत्यता यह है कि अधिनस्थ न्यायालय में वादी एवं प्रतिवादीगण द्वारा आपसी सहमति के आधार पर राजीनामा प्रस्तुत किये जाने पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा राजीनामे के आधार पर वाद पत्र डिक्री किया है। अपीलांट अधिवक्ता का कथन मिथ्या है कि राजीनामा फर्जी था जिसके संबंध में एफ आई आर दर्ज कराई गई है परन्तु अपीलांट द्वारा तथाकथित एफ आई आर के संबंध में कोई दस्तावेज पेश नहीं किया है। इस प्रकार अपीलांट का उक्त कथन साबित नहीं है। वादग्रस्त आराजीयात पर वादी एवं प्रतिवादीगण को अपने अपने हिस्से अनुसार कब्जा काशत है। अपीलांट का उक्त वादग्रस्त भूमि पर किसी प्रकार का कोई कब्जा काशत नहीं रहा है। इसी प्रकार अपीलांट अधिवक्ता का कथन रहा कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वाद पत्र में प्राथमिक डिक्री जारी नहीं की गई। इस संबंध में यह उल्लेनीय है कि पक्षकारों द्वारा आपसी सहमति से राजीनामा पेश किये जाने की स्थिति में प्राथमिक डिक्री जारी करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है केवल मात्र राजीनामा के आधार पर वाद पत्र डिक्री किया जाता है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 व 3 द्वारा प्रस्तुत राजीनामे के आधार पर दावा वादी डिक्री किया है। आपसी सहमति के आधार पर पारित किये गये निर्णय व डिक्री में स्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत है, जिसके कारण ही अधिनस्थ न्यायालय द्वारा स्थाई निषेधाज्ञा के संबंध में किसी प्रकार का आदेश पारित नहीं किया है। वादग्रस्त आराजीयात में अपीलांट का किसी प्रकार का हक एवं अधिकार निहित नहीं है। इसलिए अपीलांट को अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान नहीं की जा सकती।


राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

अपीलांट द्वारा निराधार तथ्यो के आधार पर अपील प्रस्तुत की गई है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा सम्पूर्ण राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किया जाकर एवं राजीनामे के आधार पर वाद पत्र डिक्री किया गया है। जिसमे किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि नहीं है। अतः अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जावे।

उभयपक्ष अधिवक्तागणो की बहस पर मनन किया। अपीलाधीन आदेश एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अध्ययन किया गया। जिससे यह तथ्य सामने आये कि वादग्रस्त अपीलाधीन राजीयात खसरा न0 2823,2824,2846,2849 एवं 2850 कुल किता 6 कुल रकबा 1.22 है0 वाके मुंम अमावरा तहसील बामनवास मुताबिक जमाबंदी सम्वत 2064-67 व 2068 से 2071 मे फाबूली मूल्या हिस्सा 1/2, गोविन्दा पुत्र जीवन हिस्सा 1/2 जाति बैरवा सा. देह खातेदार दर्ज है। फाबूली बेवा मूल्या की मृत्यु के उपरान्त विरासत का नामा0 संख्या 1450 दिनांक 20.10.11 को मुस्या पुत्र मूल्या हिस्सा 1/2 के नाम स्वीकार हुआ है। जिसका नोट जमाबंदी सम्वत 2068-71 मे अंकित है। मुताबिक जमाबंदी सम्वत 2064-67 व 2068 से 71 मे अपीलांट के पिता गोविन्दा का 1/2 हिस्सा दर्ज है। जबकि वादी द्वारा खातेदार गोविन्दा के वारिसान को अधिनस्थ न्यायालय मे पक्षकार नहीं बनाया है। इस तथ्य को अधिनस्थ न्यायालय द्वारा भी अनदेखा किया है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री से अपीलांटगण के हक एवं अधिकार प्रभावित होना साबित है। इस प्रकार अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील धारा 96 के प्रावधानो के अन्तर्गत पोषनीय है तथा अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री निरस्त किये जाने योग्य है तथा प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायोचित है कि प्रकरण मे गोविन्दा पुत्र नानगा के विधिक वारिसान को आवश्यक पक्षकार बनाते हुए उभयपक्ष को साक्ष्य सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए पुनःविधि सम्मत निर्णय पारित किया जावे।

अतः अपील अपीलांट रिमाण्ड योग्य होने से रिमाण्ड की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय उप जिला कलेक्टर बामनवास के प्रकरण संख्या 2/12 मे पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 13.5.16 को अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण मे मृतक गोविन्दा पुत्र नानगा बैरवा के विधिक वारिसान को आवश्यक पक्षकार बनाया जाकर, उभयपक्ष को साक्ष्य सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए पुनःविधि सम्मत निर्णय पारित करे। उभयपक्ष को पाबंद किया जाता है कि वे अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 16.6.2026 को उपस्थित होना सुनिश्चित करे।

निर्णय आज दिनांक 14.5.2026 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(लक्ष्मी कान्त बालोत)
राजस्व अपील प्रविधिकारी
सवाई माधोपुर